हिन्दी दैनिक

# लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 168 लखनऊ, गुरूवार 12 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

## संक्षिप्त समाचार

### मायावती पर आपत्तिजनक पोस्ट, बीएसपी कार्यकर्ता ने दर्ज करवाया मुकदमा

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर एक कार्यकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर श्रेया यादव नाम की फेसबुक आईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कैंट विधानसभा अध्यक्ष गंगाराम वर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 9 फरवरी को दोपहर करीब 4 बजे दामोदर नगर, आलमबाग स्थित कैंट विधानसभा प्रभारी देवेश कुमार गौतम के आवास पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। इसी दौरान मोबाइल पर फेसबुक देखते समय एक पोस्ट पर उनकी नजर पड़ी, जो श्रेया यादव नाम की फेसबुक आईडी से की गई थी।

# योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया, 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट बुधवार को पेश किया जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है। सदन के समक्ष बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के लिए हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसे राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 18वीं विधानसभा का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। इस बजट में सरकार ने रोजगार, अवस्थापना विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों को खास तवज्जो दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तुत 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 12.2 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा, इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5 प्रतिशत है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा तीन प्रतिशत निर्धारित की गई है। यह सीमा 2030–31 तक प्रभावी रहेगी। खन्ना ने प्रमुख मदों में किये गये आवंटन का जिक्र करते हुए कहा, शिक्षा तथा चिकित्सा के लिए किया गया आवंटन कुल बजट का क्रमश: 12.4 तथा छह प्रतिशत है। इसके अलावा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटित धनराशि कुल बजट की नौ प्रतिशत है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के विकास के लिये अथक परिश्रम किया है। वित्त मंत्री ने कहा कानून–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 1374 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय शिक्षा के लिए 14997 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज में से 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहे हैं। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 1023 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपये और असाध्य रोगों के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सकीय सुविधा के लिए 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37956 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वित्त वर्ष 2025–26 के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8641 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शनश योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आयुष सेवाओं

के लिए लगभग 2867 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वित्त वर्ष 2025 26 के मुकाबले 13 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट व स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 2374 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत अवस्थापना विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्चयून 500 कंपनियों के निवेश के लिए घोषित प्रोत्साहन नीति 2023 के क्रियान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें 35280 करोड़ रुपये का निवेश होने एवं 53263 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) की योजनाओं के लिए 3822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2025–26 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिए 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। नई योजना श्एक जनपद, एक व्यंजनश के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। खन्ना ने बताया कि हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए करीब 541 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–26 की तुलना में पांच गुना है। वित्त वर्ष 2026–27 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के 30 हजार अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य है। कंबल उत्पादन केंद्र गोरखपुर के आधुनिकीकरण के लिए नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिए सात करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक की योजनाओं के लिए 2059 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2025–26 की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। कृत्रिम मेधा (एआई) के क्षेत्र में विकास के लिए उत्तर प्रदेश एआई मिशन की शुरुआत की जा रही है जिसके लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

# सरकार बोली-वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा नहीं कर सकते

## सुप्रीम कोर्ट में कहा, उनकी जेल में 24 बार जांच हुई, वे पूरी तरह फिट

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। सोनम वांगचुक की

हिरासत से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वांगचुक को फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सरकार से वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा करने के बारे में पूछा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की जेल नियमावली के तहत अब तक करीब 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वांगचुक पूरी तरह फिट हैं। उन्हें केवल डाइजेशन (पाचन) की समस्या और संक्रमण हुआ था, जिसका इलाज किया गया है। मेहता ने कहा कि इस तरह की समस्या को अपवाद मानकर उन्हें रिहा किया गया तो आगे अन्य लोग भी इस तरह की मांग करेंग। उन्होंने कहा कि जिन आधारों पर वांगचुक को हिरासत में लिया गया था, वे अभी भी कायम हैं। इसलिए स्वास्थ्य कारणों से रिहाई संभव नहीं है और ऐसा करना सही भी नहीं होगा। 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 26 वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तब से वे जोधपुर जेल में हैं। इन प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 150 से अधिक लोग घायल हुए थे।

# अमीरा इंडिया कंपनी के एमडी और निदेशक भगोड़ा घोषित

## बैंकों को लगाया चूना, 123 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगी ईडी

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। विशेष न्यायालय (पीएमएलए/एफईओए), राउज एवेन्यू जिला न्यायालय ने करण ए चनाना (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) और अनीता डिंग (मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्णकालिक निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के तहत आरोपी व्यक्तियों/कंपनियों की 123.85 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। ईडी, गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने न्यायालय में करण ए चनाना और अनीता डिंग को एफईओए अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए आवेदन दिया था। हाल ही में ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने करण ए चनाना के खिलाफ विश्व भर में उनकी संपत्ति का पता लगाने और उसे फ्रीज करने के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (बीएस एंड एफबी), द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने उक्त मामले की जांच शुरू की थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशकों/प्रवर्तकों/कर्मचारियोंऔर अन्य के माध्यम से धन की हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात व धोखाधड़ी के जरिए कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को लगभग 1201.85 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान पहुंचाया है। अमीरा फूड्स समूह ब्रांडेड पैकेटबंद खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से भारतीय बासमती चावल के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में था। ईडी की जांच में पता चला कि अमीरा फूड्स ग्रुप ने कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से लगभग 1201. 85 करोड़ रुपये के भारी बैंक ऋण/नकद ऋण लिए थे। इसके बाद 2017 में यह निष्पादित (एनपीए) हो गया। ईडी ने धन शोधन के अपराध में शामिल आरोपियों और कंपनियों की पहचान कर ली है। जांच में यह भी पता चला है कि मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों/शेयरधारकों/ निदेशकों ने धन शोधन का अपराध किया है। इस मामले में 21 व्यक्तियों/कंपनियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोग शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा, ईडी की जांच में अपराध की आय के रूप में संपत्ति/परिसंपत्तियों की पहचान की गई है। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 131.51 करोड़ रुपये है, जिसकी न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है। एफईओए के तहत ईडी की जांच में पता चला है कि करण ए. चनाना और अनीता डिंग भारत छोड़कर जा चुके हैं। यह भी पुष्टि हो गई है कि वे क्रमशः यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। आरोपी आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बच रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ गैर–जमानती गिरफ्तारी वारंट और लुक–आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं। करण ए. चनाना और उनके परिवार के सदस्यों की विदेशी संपत्तियों सहित अन्य संपत्तियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

# वृंदावन में उद्घाटन से पहले ही जल उठा होटल, लपटों से दहशत में आए लोग; तीन बच्चे झुलसे

बीएनई

मथुरा। वृंदावन के रुक्मिणी विहार स्थित नवनिर्मित होटल सिद्धि विनायक में बुधवार शाम को उस समय हड़कंप मच गया, जब होटल के उद्घाटन से पहले पूजन के बाद भीषण आग लग गई। अग्निकांड में दो किशोर सहित तीन लोग झुलस गए, जबकि एक महिला चोटिल हो गई। दमकल की सात गाड़ियों ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। होटल में फंसे लोगों को क्रेन से रेस्क्यू कर निकाला। डीएम ने होटल की जांच के आदेश दिए हैं। रुक्मिणी विहार के सेक्टर 1 स्थित होटल सिद्धि विनायक का बुधवार शाम को उद्घाटन समारोह था। होटल स्वामी ने परिवार के लोगों के साथ पूजन किया। होटल मालिक राया निवासी सुभाष अग्रवाल और उनके परिवार एवं रिश्तेदार पूजन में शामिल थे। होटल में पूजन

करने के कुछ ही समय बाद अचानक भूमितल के सामने के हिस्से में आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग की लपटें तीसरी मंजिल तक पहुंच गईं। भीषण आग को देख चीख पुकार मच गई। जिस समय आग लगी उस समय पूजन के बाद कुछ लोग होटल में आराम कर रहे थे। बच्चे दूसरी मंजिल पर खेल रहे थे। होटल मालिक की सूचना पर पहुंची दमकल की सात गाड़ियों ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं होटल में फंसे लोगों को छत के रास्ते होटल के पीछे की तरफ से क्रेन से रेस्क्यू कर नीचे उतारा। हादसे में होटल मालिक के भांजे का लड़का मथुरा के कच्ची सड़क निवासी 12 वर्षीय समर्थ, गोवर्धन रोड मथुरा निवासी 18 वर्षीय कार्तिक और राया निवासी 16 वर्षीय जिया झुलस गए वहीं 28 वर्षीय कविता घायल हो गईं। पुलिस ने झुलसे कार्तिक और समर्थ को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से उन्हें मथुरा के लिए रेफर कर दिया। परिजन उन्हें मसानी स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए। जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। होटल मालिक सुभाष चंद्र अग्रवाल ने बताया कि होटल में अभी एक माह का काम बाकी था। आज परिवार के साथ उन्होंने पूजन कराया था। उसके कुछ ही समय बाद शॉर्टसर्किट से आग लग गई है। घटनास्थल पर डीएम सीपी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व पंकज वर्मा, सीओ पीतम पाल सिंह एवं चार थाने का पुलिस बल पहुंच गया। डीएम सीपी सिंह ने कहा कि होटल में उद्घाटन के दौरान आग लगी है। इसमें तीन बच्चे झुलस गए हैं व एक महिला घायल हुई है। होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जांच कराई जाएगी कि इन्होंने एनओसी ली है या नहीं। घटना की जांच कर दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

# चाइनीज मांझे से मौतों पर लखनऊ हाईकोर्ट सख्त

## राज्य सरकार को घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नियम बनाने का निर्देश

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों और चोटों पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सरकार से पूछा कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की गई है। न्यायालय ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि वह चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग को रोकने के साथ–साथ पीड़ितों को उनके मेडिकल खर्च सहित मुआवजा देने पर भी विचार करें। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अभिभावकों और बच्चों में खतरनाक चाइनीज मांझे के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने पारित किया। यह आदेश स्थानीय वकील एम.एल. यादव द्वारा 2018 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया। याचिकाकर्ता ने हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए चाइनीज मांझे पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। न्यायालय में समाचार पत्रों की रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गईं, जिनमें चाइनीज मांझे से लगभग 10 लोगों के घायल होने और कुछ मौतों का जिक्र था। राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया कि सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है और हाल ही में चाइनीज मांझे की बिक्री व इस्तेमाल रोकने के आदेश जारी किए हैं। इस पर, न्यायालय ने सवाल किया कि जब लोग चाइनीज मांझे से घायल होते हैं या मर जाते हैं, तभी राज्य सरकार हरकत में क्यों आती है। कोर्ट ने सरकार को ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए एक उचित व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया।

# जमानत याचिका में आपराधिक इतिहास बताना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता पर दिया बड़ा आदेश

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमानत की मांग करने वाले हर अभियुक्त को अपने आपराधिक इतिहास का पूरा खुलासा हलफनामे के साथ करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि जमानत याचिका दाखिल करते समय आरोपी की जिम्मेदारी है कि वह सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से अदालत के सामने रखे। यदि कोई तथ्य छिपाया जाता है या आंशिक जानकारी दी जाती है, तो इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि जमानत पर फैसला केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि न्यायिक विवेक का गंभीर प्रयोग है। इसलिए अदालत के समक्ष पूरी सच्चाई रखना आवश्यक है।

जमानत आवेदन में क्या–क्या बताना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जमानत याचिका में निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप से शामिल हों:–

FIR नंबर और तारीख

संबंधित पुलिस थाने का नाम

जांच एजेंसी द्वारा लगाई गई धाराएं

आरोपित अपराध की अधिकतम सजा

लंबित गैर–जमानती वारंट या घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) जैसी कार्यवाही का विवरण

न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना अनिवार्य

अदालत ने यह भी कहा कि इस निर्णय की प्रति सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को भेजी जाए,

ताकि वे अपने नियमों में आवश्यक संशोधन या प्रशासनिक दिशा–निर्देश जारी कर सकें। यह आदेश उस मामले में आया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फर्जी डिग्री प्रमाणपत्र जारी करने के आरोपी को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्ण और ईमानदार खुलासा अनिवार्य है। जमानत का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा की शर्त पर ही मिल सकता है।

# कानपुर से लखनऊ आकर युवक ने की आत्महत्या

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बुधवार को 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान आदित्य सिंह (22) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से कानपुर के घाटमपुर का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक आदित्य कानपुर पॉलिटेक्निक में कोचिंग कर रहा था। दो दिन पहले वह लखनऊ आया था और अपने मामा के लड़के शिवम के यहां ठहरा हुआ था। शिवम लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस के पास रहता है। यहीं रह कर पढ़ाई करता है। दोस्तो ने बताया कि आदित्य मंगलवार रात भर जागता रहा। बुधवार सुबह छत पर लगे टीन शेड में नायलॉन की रस्सी के सहारे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब काफी देर तक वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो भाई को शक हुआ। जब ढूंढते हुए ऊपर पहुंचा तो देखा कि वह फंदे से लटक रहा है। आनन–फानन में पुलिस को सूचना दी गई।

# संपादकीय

## देश की सुरक्षा और सच-झूठ की परीक्षा

पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब श्फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनीश पर सियासी घमासान अब सच और झूठ की परीक्षा में तब्दील हो चुका है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यह किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस किताब की प्रति पिछले हफ्ते ही संसद में लेकर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह किताब देंगे, ताकि वे खुद उन बातों और तथ्यों को पढ़ सकें, जिन्हें लोकसभा में पढ़ने से राहुल गांधी को रोका गया। लेकिन नरेन्द्र मोदी इसके बाद लोकसभा में पहुंचे ही नहीं और न ही राहुल गांधी से उनका सामना हुआ। हालांकि यह एक अच्छा मौका नरेन्द्र मोदी के पास था, जब वे एक साथ अपनी देशभक्ति, बहादुरी और 56 इंची सीने की सच्चाई देश–दुनिया को दिखा देते। राहुल गांधी का कहना है कि नरेन्द्र मोदी एक किताब से डर गए, क्योंकि इसमें चीन के घुसपैठिया अभियान की हकीकत बयां की गई है। श्री मोदी चाहते तो राहुल गांधी से ये किताब लेकर साबित कर देते कि वे डरे हुए नहीं हैं और जो कुछ उस किताब में लिखा है उसे भी पढ़ लेते। अगर कुछ गलत लिखा है तो उसकी सच्चाई बता देते, इससे उनका ही हाथ ऊंचा होता। लेकिन बजाए इतना सीधा सा काम करने के, अब इस मामले को कानूनी पचड़े में उलझा दिया गया है। अब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब की सॉफ्ट कॉपी के ऑनलाइन प्रसारित होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है, श्हमने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिलने पर जांच शुरू की। किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा तैयार की गई लगती है, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से यह अभी अप्रकाशित है। स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच चल रही है। गौरतलब है कि किताब में जनरल नरवणे ने लिखा है कि 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव के दौरान जब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य नेताओं को जानकारी दी कि, चीनी टैंक आ रहे हैं, तो लंबे समय तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला। करीब ढाई घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया–जो उचित समझो, वो करोश। राहुल गांधी इसी पर सरकार से जवाब चाह रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, मुझे यकीन है कि यह किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई।श उन्होंने राहुल गांधी से कहा, जो किताब का दावा कर रहे हैं, उसे सदन में पेश करें, हम देखना चाहते हैं। सरकार द्वारा ऐसी किसी किताब के छपे होने के दावे को खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने 4 फरवरी को संसद परिसर में किताब की प्रकाशित प्रति दिखाई और पत्रकारों से कहा, देखिए, किताब है, सरकार कह रही है कि किताब नहीं है। बता दें कि फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा है। जनरल नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख रहे। किताब में उनकी 40 साल की सेवा, सिक्किम में चीन से पहला आमना–सामना, गलवान संघर्ष, पाकिस्तान के साथ सीजफायर आदि का जिक्र है। किताब 448 पेज की है और अप्रैल 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अभी उपलब्ध नहींश लिखा था। बहरहाल, दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच–पड़ताल में करेगी कि आखिर यह किताब पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन लोगों तक कैसे पहुंच रही है। किताब को प्रकाशित करने की जरूरी मंजूरी रक्षा मंत्रालय से अभी नहीं मिली है। इसलिए यह लीक या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली पुलिस के पास और कोई जरूरी काम बचे ही नहीं है। हालांकि सोमवार को ही कम से कम पांच हत्याओं के मामले दिल्ली में घटित हुए हैं, इसके अलावा चोरी, छीना–झपटी, झगड़े–फसाद, लड़कियों की सुरक्षा जैसे अनगिनत मामले हैं, जिन्हें संभालने या कम करने के लिए पुलिस बल की जरूरत होती है। मगर इन सबको छोड़कर अमित शाह के गृह मंत्रालय ने अपनी पुलिस को इस काम में लगाया है कि किताब का पीडीएफ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। इस बीच किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की भी सफाई आई है। पेंगुइन प्रकाशन ने कहा है कि इस किताब के प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और यह पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर 2023 में मनोज नरवणे का लिखा एक ट्वीट भी सामने आ गया है, जिसमें वे अपनी किताब के प्रकाशन की जानकारी दे रहे हैं और ऑनलाइन बुक करने का आग्रह भी कर रहे हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने यही ट्वीट पत्रकारों को सुनाया भी और साफ कहा है कि या तो मनोज मुकुंद नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूर्व आर्मी चीफ झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पेंगुइन का कहना है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन किताब अमेजन पर उपलब्ध है, मुझे पेंगुइन से ज़्यादा नरवणे जी पर भरोसा है।

# राशिफल

मेष :– किसी श्रेष्ठजन के प्यार से मन प्रसन्न होगा। किसी की कटु वाणी मन को दुखित कर सकती है। उच्च महत्वकांक्षाएं व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेंगी। आलस्य कतई न करें।

बृषभ :– भौतिक महत्वकांक्षाएं अभाव का एहसास कराएंगी। परिजनों से कुछ भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। अच्छी योजनाओ द्वारा महत्वपूर्ण कायरें को समयानुकूल पूर्ण करेंगे।

मिथुन :– भावनाओं पर नियंतग्रख अपने दायित्वों के प्रति सजग होना प्रगति का सूचक है। बचकाना स्वभाव महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकाग्रता का अभाव पैदा करेगा। शिक्षा–प्रतियोगिता में परिश्रम का लाभ मिलेगा।

कर्क :– महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। कुछ नयी आकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। भौतिक–सुख साधन में व्यय संभव। परिजनों से किसी प्रकार की शिकायत पर खुलकर बात करें।

सिंह :– भावना से उद्वेलित मन निकट संबंधों के सुख–दुख के प्रति चिंतित होगा। पूर्वाग्रहवश संबंधियों के प्रति नकारात्मकता को न पालें। भविष्य संबंधी कुछ चिंताएं मन में नकारात्मक विचार ला सकती हैं।

कन्या :– नये संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। जीविका क्षेत्र में मन आर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रयत्नशील होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कार्य समय से पूर्ण करें।

तुला :– कुछ नयी अभिलाषाएं आपको उत्साहित करेंगी। शासन–सत्ता की दिशा में केंद्रित लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी महत्वपूर्ण दायित्व की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था हेतु मन चिंतित होगा।

वृश्चिक :– किसी पुराने संबंध के प्रति विशेष निकटता की अनुभूति करेंगे। क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां अर्थिक सुदृढ़ता हेतु प्रेरित करेंगी। भावनाप्रधान मन रिश्तों से सहज ही प्रभावित हो जाता है।

धनु :– रोजगार क्षेत्र में आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं सार्थक होती हुई नजर आएंगी। श्रेष्ठजनों से नजदीकियां पैदा होंगी। व्यावसायिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ प्रबल इच्छाएं आपको उद्वेलित करेंगी।

मकर :– सामाजिक गतिविधियों में आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी। अच्छी भावनात्मक अभिव्यक्ति से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। राजनीति से जुडे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभ :– पुरानी समस्याओं को हल कर सुख की अनुभूति करेंगे। शासन–सत्ता से जुड़े लोगों को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पूजा–पाठ में पूरा दिन मन केंद्रित होगा। नये दायित्वों की पूर्ति होगी।

मीन :– पिता के सहयोग से मुश्किल दिनों में राहत मिलेगी। बालसुलभता व असंयमित शब्दों का प्रयोग संबंधों में कटुता लाएगा। आकस्मिक नई आशंकाओं से प्रभावित मन कोई गलत निर्णय ले सकता है।

# क्यों गायब हो रहे बच्चे?

–डॉ. प्रियंका सौरभ

हरियाणा में गुमशुदगी के बढ़ते मामले अब केवल पुलिस रजिस्टरों या अखबारों की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहे हैं। ये मामले उन हजारों परिवारों की अनकही पीड़ा हैं, जिनके घरों से कोई सदस्य काम, पढ़ाई या रोज़मर्रा के काम के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हर दिन औसतन 12 बच्चों का लापता होना और वर्ष 2025 में 17,500 से अधिक गुमशुदगी के मुकदमों का दर्ज होना, किसी भी संवेदनशील समाज के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए। यह स्थिति न सिर्फ कानून–व्यवस्था की चुनौती है, बल्कि सामाजिक ताने–बाने पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। गुमशुदगी का सबसे भयावह पहलू यह है कि इसके पीछे अब केवल व्यक्तिगत विवाद, घरेलू कारण या आकस्मिक घटनाएं नहीं रहीं। जांच में बार–बार यह संकेत मिल रहे हैं कि कई मामलों की जड़ें मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों से जुड़ी हुई हैं। पुलिस के अनुसार करीब 75 प्रतिशत मामलों को ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन शेष 25 प्रतिशत अधूरे मामले ही असली चिंता का कारण हैं। यही वे मामले हैं जिनमें लापता व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिलता और जिनके पीछे अंतरराज्यीय गिरोह, अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां और आर्थिक शोषण के नेटवर्क काम कर रहे होते हैं। विशेष चिंता इस बात की है कि महिलाएं और नाबालिग बच्चे इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बन रहे हैं। बेहतर रोजगार, उज्ज्वल भविष्य या शिक्षा का सपना दिखाकर बच्चों और युवाओं को उनके घरों से दूर ले जाया जाता है। कई बार माता–पिता खुद मजबूरी में बच्चों को ऐसे एजेंटों के हवाले कर देते हैं, जिन्हें वे भरोसेमंद समझते हैं। बाद में वही भरोसा परिवारों के लिए जीवनभर का पछतावा बन जाता है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों से जुड़े नेटवर्क इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह समस्या स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर फैले संगठित अपराध का हिस्सा है। हरियाणा में भिक्षावृत्ति और बालश्रम से मुक्त कराए गए 350 से अधिक बच्चों के मामले इस सच्चाई को और उजागर करते हैं। चौक–चौराहों, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों पर दिखाई देने वाले ये बच्चे किसी संयोग का परिणाम नहीं हैं। ये एक सुनियोजित तंत्र के तहत यहां लाए जाते हैं, जहां उनसे काम कराया जाता है या उन्हें भिक्षावृत्ति में धकेला जाता है। इनसे होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा गिरोह या प्लेसमेंट एजेंसियों के पास चला जाता है, जबकि बच्चों को अमानवीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर किया जाता है। यह भी गौर करने योग्य है कि मानव तस्करी अब अकेला अपराध नहीं रहा। पुलिस और जांच एजेंसियों का मानना है कि नशा तस्करी, साइबर अपराध, एक्सटॉर्शन और मानव तस्करी जैसे अपराध अब एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही नेटवर्क कई तरह के अवैध कामों को अंजाम दे रहा है। यही कारण है कि गुमशुदगी के मामलों की जांच अब संगठित अपराध के नजरिये से की जा रही है। यह बदलाव सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसके लिए संसाधनों, तकनीक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी उतनी ही जरूरत है। हरियाणा पुलिस द्वारा वर्ष 2026 के लिए तैयार किया गया अपराध नियंत्रण रोडमैप उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाता है। संगठित अपराधियों पर कड़ी निगरानी, तकनीक के माध्यम से पहचान और ट्रैकिंग, अंतरराज्यीय समन्वय और समयबद्ध जांच जैसे कदम निस्संदेह आवश्यक हैं। पुलिस महानिदेशक का यह स्पष्ट संदेश कि बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भरोसा पैदा करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल प्रशासनिक सख्ती से इस गहरी समस्या को पूरी तरह सुलझाया जा सकता है?

सच्चाई यह है कि गुमशुदगी और मानव तस्करी जैसी समस्याएं केवल कानून–व्यवस्था के दायरे में सुलझने वाली नहीं हैं। इनके पीछे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे कारण भी काम करते हैं। जब परिवारों के पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं और बेहतर जीवन का सपना उन्हें हर दिन बेचैन करता है, तब वे अक्सर गलत हाथों में फंस जाते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि उन परिस्थितियों को बदलने की भी होनी चाहिए, जो लोगों को असुरक्षित बनाती हैं। समाज की भूमिका यहां सबसे अहम हो जाती है। अक्सर लोग लापता बच्चों या

संदिग्ध गतिविधियों को देखकर भी चुप रह जाते हैं। "यह किसी और का मामला है" जैसी सोच अपराधियों के हौसले बढ़ाती है। यदि समय रहते संदिग्ध प्लेसमेंट एजेंसियों की सूचना दी जाए, भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को नजरअंदाज न किया जाए और लापता होने की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाए, तो कई मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। जागरूक समाज ही किसी भी अपराध के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकता है। बाल अधिकार विशेषज्ञों का यह कहना बिल्कुल सही है कि बच्चों को तस्करी से मुक्त कराना केवल पहला कदम है। असली चुनौती उनके पुनर्वास, शिक्षा और मानसिक काउंसलिंग की है। तस्करी का शिकार हुए बच्चे गहरे मानसिक आघात से गुजरते हैं। यदि उन्हें समय पर सही देखभाल और अवसर नहीं मिले, तो वे दोबारा उसी अंधेरे चक्र में फंस सकते हैं। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सम्मानजनक हो। हरियाणा में गुमशुदगी के मामले हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास और आर्थिक प्रगति के दावों के बीच कहीं हम मानवीय मूल्यों को तो नहीं खोते जा रहे। यह समस्या केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हर उस परिवार की कहानी है, जो आज भी किसी दरवाजे की आहट पर उम्मीद लगाए बैठा है। यदि अब भी इसे केवल एक खबर या एक प्रशासनिक चुनौती समझकर नजरअंदाज किया गया, तो आने वाले वर्षों में इसकी कीमत कहीं ज्यादा भारी होगी। समय की मांग है कि गुमशुदगी को अपराध के साथ–साथ मानवीय संकट के रूप में देखा जाए। सरकार, पुलिस, समाज और नागरिकसभी को अपनी–अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई बच्चा, कोई महिला या कोई नागरिक यूं ही गुम न हो जाए और उसका परिवार जिंदगी भर इंतजार करने को मजबूर न रहे।

# मोदी-शाह के दौरों के बावजूद भगवा पार्टी का मनोबल अधिक मजबूत नहीं हुआ

–तीर्थंकर मित्रा

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हराने की बात कहना भाजपा के लिए जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, भले ही भाजपा नेता इस साल अप्रैल–मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने की बात कर रहे हों। पूरी कोशिश करने के बावजूद लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद, भगवा पार्टी की 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीदें सत्ता विरोधी भावना, पूरे बंगाल में हिंदू एकजुटता, और टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कहानी पर टिकी हैं। इन मुद्दों के आधार पर, इस चुनावी राज्य में भाजपा का प्रचार टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करिश्मे और उनकी सरकार के उन लोकप्रिय परियोजनाओं के खिलाफ होगा, जिनसे उन्हें चुनावी फायदा हुआ था। टीएमसी के इन चुनावी प्लेटफॉर्म से पार पाना भगवा खेमे के लिए अब तक की सबसे मुश्किल चुनावी परीक्षा होगी। टीएमसी नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना भाजपा के लिए सबसे अच्छा दांव लगता है क्योंकि वह चुनाव प्रचार शुरू करने वाली है। रुपये के बदले नौकरी देने का आरोप और टीएमसी के पूर्व महासचिव और शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के साथी के घर से मिले नकदी के बंडल और आरजीकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक लेडी डॉक्टर के बलात्कार और उसकी हत्या ने टीएमसी नेतृत्व को मुश्किल में डाल दिया है। इसके साथ ही, भगवा खेमे की नजर सत्ताविरोधी कारक और हिंदू वोटों के एकजुट होने पर है। सत्ताविरोधी कारक इसलिए बेअसर है क्योंकि राज्य के भगवा खेमे के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जा सके। भगवा खेमे का हिंदू वोटों का समीकरण सही नहीं है। हो सकता है कि समुदाय सत्ताधारी सरकार से खुश न हो, लेकिन इसके भाजपा को एक साथ वोट देने की उम्मीद कम है। हालांकि विपक्ष के नेता, शुभेंदु अधिकारी अब तक के सबसे लोकप्रिय और दिखने वाले भाजपा नेता हैं, लेकिन उनके अपने खेमे में भी उनके विरोधी हैं। राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया है कि वे तब से भाजपा में हैं जब शुभेंदु तृणमूल में थे और ममता बनर्जी के खास सिपहसालार थे।

इसके अलावा, टीएमसी संगठन के मामले में भाजपा से बहुत आगे है। तृणमूल के सांगठनिक नेटवर्क ने पार्टी को संभाला, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी राज्य में आए हों और चुनावी माहौल को और गरमाया हो। हालात ऐसे हो गए हैं कि भगवा खेमा अपनी सांगठनिक कमजोरी को ठीक करने के लिए राज्य से किसी नेता को नहीं ला सका। इसने पिछले सितंबर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी चुना और उन्हें पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने का काम सौंपा। केंद्रीय नेतृत्व के इस आदमी ने पार्टी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन राज्य के भगवा खेमे के सूत्रों ने बताया कि यादव को उन्हें दिए गए काम के लिए समय काफी नहीं लगा। सूत्रों ने बताया कि राज्य भाजपा के पास बूथ लेवल के इतने कार्यकर्ता नहीं हैं जिनकी मौजूदगी या गैरमौजूदगी मतदान के दिन किसी उम्मीदवार की जीत या हार तय कर सके। अगर ये कार्यकर्ता 2021 के विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन बाहर रहते तो भगवा खेमे में विधायकों की संख्या और ज़्यादा होती। इस बीच, तृणमूल प्रमुख अपनी 2021 की रणनीति को जारी रखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को श्बाहरीश कहती रही हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) की पृष्ठभूमि में, पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय कोई भी श्बाहरीश का टैग नहीं लगवाना चाहता। गुमशुदा लोगों ने पहले ही भाजपा के विधायकों की संख्या कम कर दी है। ममता बनर्जी का करिश्मा और टीएमसी की लगातार तीन जीत आने वाले चुनावों में भगवा खेमे के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए बहुत से लोगों को उत्सुक नहीं करेंगी।

# मोदी जी, कृपया कभी तो प्रधानमंत्री की तरह बोलिए

–अनिल जैन

राज्यसभा में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, उसमें भी न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा और शालीनता का समावेश था और न ही पद की गरिमा व लोकतांत्रिक परंपरा की कोई झलक थी। स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का समापन करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मुद्दों पर अपनी सरकार का नजरिया पेश करते हैं।

नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के दौरान का उनका एक भी ऐसा भाषण याद नहीं आता जो उन्होंने इस विशाल देश के प्रधानमंत्री की तरह दिया हो। अधूरा सच, सफेद झूठ, आधी–अधूरी जानकारी के आधार पर गलत बयानी, तथ्यों की मनमाने ढंग से तोड़–मरोड़, परनिंदा, पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति हिकारत का भाव, नए–नए शिगूफे, स्तरहीन मुहावरे, राजनीतिक विरोधियों पर छिछले कटाक्ष, नफरत भरी सांप्रदायिक तल्खी, धार्मिक व सांप्रदायिक प्रतीकों का इस्तेमाल और भरपूर आत्म प्रशंसा! यही सब प्रमुख तत्व होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में। मौका चाहे देश में हो या विदेश में, संसद में हो या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर, चुनावी रैली हो या कोई और अवसर– हर जगह उनके भाषण में अहंकारयुक्त हाव–भाव के साथ यही सारे तत्व हावी रहते हैं। पिछले सप्ताह गुरूवार (5 फरवरी) को राज्यसभा में दिया गया भाषण भी इसका अपवाद नहीं रहा। वैसे तो मोदी को संसद के दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देना था, लेकिन लोकसभा में 4 फरवरी को उन्होंने भाषण नहीं दिया। ऐसा उन्होंने श्लोकसभा स्पीकर के कहने परश किया। स्पीकर ओम बिड़ला ने बेहद हास्यास्पद और शर्मनाक आशंका जताई थी कि प्रधानमंत्री अगर सदन में भाषण देने आएंगे तो कांग्रेस की कुछ महिला सांसद उन पर हमला कर सकती हैं। स्पीकर की इस आशंका से वह प्रधानमंत्री डरकर सदन में नहीं आए, जिसने तीन साल पहले 10 फरवरी, 2023 को संसद में ही अपनी पीठ थपथपाते हुए बेहद फूहड़ अंदाज में कहा था, देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। बहरहाल राज्यसभा में उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो भाषण दिया, उसमें भी न तो न्यूनतम संसदीय मर्यादा और शालीनता का समावेश था और न ही पद की गरिमा व लोकतांत्रिक परंपरा की कोई झलक थी। स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का समापन करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित मुद्दों पर अपनी सरकार का नजरिया पेश करते हैं। इसी क्रम में वे बहस के दौरान विपक्ष के आरोपों और आलोचनाओं का भी जवाब देते हैं। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं किया। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने इस गंभीर मौके पर भी एक मोहल्ला स्तर के नेता की तरह चुनावी भाषण दिया।

कुछ साल पहले फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि श्देश को असली आजादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मिली है।श कंगना की इस बात पर खुश होकर मोदी ने उन्हें सांसद बनवा दिया और गुरूवार को राज्यसभा में कंगना द्वारा कही बात की तर्ज पर ही यह जताने की कोशिश की कि देश ने जो कुछ तरक्की की है, वह उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद की ही है। उन्होंने कहा कि उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए उनमें किसी के पास देश को लेकर न तो कोई सोच थी, न कोई दृष्टि और न ही इच्छाशक्ति। उन्होंने देश को बर्बाद करके रखा हुआ था। उन्होंने कहा, श्मैं देशवासियों का आभारी हूं कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया।

हमारी काफी शक्ति उनकी (पूर्व प्रधानमंत्रियों की) गलतियों को ठीक करने में लग रही है। उनके समय जो देश की छवि बनी थी, उसे धोने में मेरी ताकत लग रही है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की आलोचना व निंदा करने का तो मोदी पर मानो जुनून सवार रहता है और इस सिलसिले में जो मुंह में आता है वह बोल जाते हैं। ऐसा करने में वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उनकी अशोभनीय गलतबयानी से देश–दुनिया में उनकी खिल्ली उड़ेगी और लोग उनकी पढ़ाई–लिखाई व उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाएंगे। राज्यसभा में दिए अपने भाषण में भी मोदी ऐसा करना नहीं भूले। इस सिलसिले में उन्होंने इंदिरा गांधी के ईरान में दिए गए एक भाषण के हवाले से कहा कि, श्जवाहरलाल नेहरू के समय देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी और नेहरू कहते थे कि मेरे सामने 35 करोड़ समस्याएं हैं।श इसी तरह इंदिरा गांधी के समय देश की जनसंख्या 57 करोड़ थी और इंदिरा जी ने कहा था कि, श्मेरे सामने 57 करोड़ समस्याएं हैं।श मोदी का यह बताना या तो उनकी क्षुद्रता का परिचायक है या फिर उनकी नासमझी का। यह उनके भाषण के नोट्स बनाने वाले नौकरशाहों की शरारत भी हो सकती है कि उन्होंने मोदी को गलत नोट्स बनाकर थमा दिए हों जिन्हें मोदी ने संसद में पढ़ दिए। दरअसल नेहरू से जब किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि श्आपके सामने कितनी समस्याएं हैंश, तो नेहरू ने कहा था कि देश के 35 करोड़ लोगों की समस्याएं मेरी समस्या हैय और इसी तरह इंदिरा गांधी ने कहा

था कि देश के 57 करोड़ लोगों की समस्याओं को मैं अपनी समस्या मानती हूं। प्रधानमंत्री अपने भाषण का स्तर गिराने में यहीं नहीं ठहरे। इससे भी नीचे उतरते हुए उन्होंने कहा कि श्चोरी करना नेहरू–गांधी परिवार का पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती महात्मा गांधी का सरनेम तक चुरा लिया।श वैसे अव्वल तो कोई क्या सरनेम लगाता है, यह बहस का विषय नहीं हो सकता और संसद में तो कतई नहीं, फिर भी अगर मोदी को इसका शौक है तो उन्हें इस बारे में बोलने से पहले यह जान लेना चाहिए कि गांधी सरनेम किसी जाति या संप्रदाय विशेष में नहीं होता है बल्कि यह इत्र–फुलेल से जुड़े व्यवसाय से ताल्लुक रखता है। यह सरनेम सिर्फ वैश्य वर्ग में ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिख, पारसी आदि समुदायों में भी होता है। मोदी ने यह सिलसिला सिर्फ चुनावी सभाओं तक ही सीमित नहीं रखा है। संसद में, संसद के बाहर विभिन्न मंचों पर और यहां तक कि विदेशों में भी वे विपक्षी नेताओं पर निजी हमले और अपमानजनक बातें करने से नहीं चूकते हैं। फिर, विपक्ष शासित राज्यों के प्रति उनकी सरकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार ने भी केंद्र और राज्यों के बीच खटास पैदा कर दी है।

दरअसल विरोधी दलों और उनके नेताओं के प्रति मोदी की अपमानजनक बातें शुरू में जरूर अटपटी लगती थीं। चूंकि भाजपा और मोदी ने काफी बड़ी जीत हासिल की थी, इसलिए विपक्षी नेताओं ने उनकी ऐसी बातों को यह सोचकर बर्दाश्त किया कि जीत की खुमारी उतर जाने पर प्रधानमंत्री राजनीतिक विमर्श में सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार और भाषायी शालीनता का पालन करने लगेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ और लगने लगा कि यही मोदी की स्वाभाविक राजनीतिक शैली है और वे बदलने वाले नहीं हैं, तब विपक्षी नेताओं के सब्र का बांध टूटा और उसमें सारी राजनीतिक शालीनता और मर्यादा बहती चली गई। देश में शायद ही कोई ऐसा विपक्षी मुख्यमंत्री या नेता होगा जिसके लिए पीएम ने सार्वजनिक रूप से अपमानजनक बातें या गाली–गलौज नहीं की होगी। मोदी उन्हें भ्रष्ट, परिवारवादी, लुटेरा, नक्सली, आतंकवादियों का समर्थक और देशद्रोही तक करार देने में कोई संकोच नहीं करते। इस सिलसिले में वे विपक्ष की महिला नेताओं को भी नहीं ब+ख्शते। वे उनके लिए बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। विपक्षी नेताओं के प्रति मोदी के अपमानजनक बर्ताव का ही नतीजा है कि आज केन्द्र–राज्य संबंधों किसी भी समय के मुकाबले सबसे बदतर स्थिति में हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब मोदी किसी विपक्ष शासित राज्य के दौरे पर गए तब वहां के मुख्यमंत्री उनकी आगवानी करने नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री ने तमाम विपक्षी दलों को अपने, अपनी पार्टी और देश के दुश्मन के तौर पर प्रचारित करते हुए उन्हें खत्म करने का खुला ऐलान किया है। वे हर जगह डबल इंजन की सरकार का ऐसा प्रचार करते हैं, जैसे विपक्ष की सारी सरकारें जनविरोधी, देश–विरोधी और विकास–विरोधी हैं। मोदी की इस राजनीति ने विपक्षी पार्टियों को सोचने पर मजबूर किया है। इसलिए आज अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर आंच आ रही है और उनकी बेअदबी हो रही है तो इसके लिए प्रधानमंत्री का अंदाज–ए–हुकूमत और अंदाज–ए–सियासत ही जिम्मेदार है। कितना अच्छा होता कि मोदी भाषा और संवाद के मामले में भी उतने ही नफासत पसंद या सुरुचिपूर्ण होते, जितने वे पहनने–ओढ़ने और सजने–संवरने के मामले में हैं। एक देश अपने प्रधानमंत्री से इतनी सामान्य और जायज अपेक्षा तो रख ही सकता है। उनका बाकी अंदाज–ए–हुकूमत चाहे जैसा भी हो।

# नवाचार कार्यक्रम के लिए एकेटीयू अपने संस्थानों को दे रहा 2 लाख का फंड

## -नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की है पहल, एकेटीयू इन्क्युबेटर इम्पावरमेंट स्कीम के तहत एक वित्तीय वर्ष में 20 संस्थानों को मिलेगा योजना का लाभ

**लखनऊ ब्यूरो**

लखनऊ। डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को ऊंची उड़ान देने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इसके लिए माननीय कुलपति प्रो0 जेपी पाण्डेय के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की कार्ययोजना तैयार की गयी है। ताकि प्रदेश के हर हिस्से के छात्र नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति से खुद को जोड़ सकें। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब ने संबद्ध संस्थानों को स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए एकेटीयू इन्क्युबेटर इम्पावरमेंट स्कीम के तहत दो लाख रूपये फंड देना शुरू किया है। इससे न केवल नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि छात्र की सोच में भी बदलाव आयेगा।

**एक वित्तीय वर्ष में 20 संस्थानों को मिलेगा फंड**

इस योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय से संबद्ध अधिकतम 20 संस्थानों को स्टार्टअप कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए 2 लाख रूपये बतौर फंड के रूप में मिलेगा। वहीं एक संस्थान एक वित्तीय वर्ष में दो बार इस फंड का लाभ ले सकता है। स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत संस्थान को इनोवेशन हब से जुड़कर उद्यमिता से संबंधित कार्यक्रम, स्टार्टअप्स पिचथॉन, हैकथॉन, बूटकैंप, स्टार्टअप प्रदर्शनी, स्टार्टअप मेलों सहित नवाचार के लिए चल रही योजनाओं आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। जिससे कि छात्रों को इस क्षेत्र में सहूलियत और सुविधा मिल सके। इस योजना का लाभ पाने के लिए संस्थानों को इनोवेशन हब की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

**इनोवेशन हब बना रहा इकोसिस्टम**

विश्वविद्यालय का इनोवेशन हब नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति और परंपरा विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए समय–समय पर हैकथॉन आयोजित कराये जा रहे हैं। ताकि अच्छे स्टार्टअप को आगे बढ़ने का मंच मिल सके। साथ ही इनोवेशन हब से काफी संख्या में स्टार्टअप्स जुड़े हैं। जिन्हें आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की जा रही है। उन्हें न केवल विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिल रहा है बल्कि कोवर्किंग स्पेस, विभिन्न प्रकार के मंच, आदि की भी सहायता दी जा रही है। इस कार्य में वित्त अधिकारी केशव सिंह डीन इनोवेशन प्रो0 बीएन मिश्रा एवं एसो0 डीन डॉ0 अनुज कुमार शर्मा के नेतृत्व में इनोवेशन हब के सीईओ महीप सिंह सहित पूरी टीम कार्य कर रही है।

# बचपन की सहेलियां ट्रेन से कटीं, एक की 6 महीने पहले हुई थी शादी

**संवाददाता**

लखनऊ। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में हादसा हो गया। यहां मनकोटी गांव के पास ट्रेन पटरी पर बचपन 2 सहेलियां कट गईं। एक लड़की की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। वह आज (11 फरवरी) ही सुबह मायके आई थी। कुछ देर बाद दोनों की डेडबॉडी ट्रेन पटरी पर मिली। ट्रेन से लड़कियों के कटने की सूचना पर गांववाले घटनास्थल पहुंच गए। घटना बेलवा रेलवे फाटक के पास की है। यह मनकोटी से करीब 1 किमी दूर है। मृतक सहेलियां रहीमाबाद के मनकोटी गांव की थीं। गांववालों के अनुसार, वे दोनों हरपल साथ ही रहती थीं। आज दोनों की साथ ही मौत हो गई। रहीमाबाद थाना पुलिस के अनुसार, मृतक युवतियों की उम्र 20 और 23 साल है। 20 वर्षीय शशि पुत्री अशर्फी लाल और 23 वर्षीय नीतू पुत्री बुद्धा की मौत हुई। इन दोनों की ट्रेन से कटने की जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे ट्रैक पार रही थीं लेकिन दूसरे एंगल पर भी जांच की जा रही है। नीतू के मायके आने के बाद दोनों घर से निकलीं और ट्रेन से टकराकर उनकी मौत हो गई। आशंका है कि दोनों ने सुसाइड किया होगा। बहरहाल जांच और पूछताछ के बाद पता चल सकेगा कि आखिर यह हादसा था या सुसाइड। पड़ोसियों का कहना है कि नीतू और शशि बचपन से ही हरपल साथ रहती थीं। नीतू की शादी 6 महीने पहले हुई थी। उसका पति इशू चंडीगढ़ में रहकर काम करता है। उसकी शादी उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के धनियाखेड़ा गांव में हुई थी। नीतू आज ही अपने मायके आई हुई थी। अपनी सहेली शशि के साथ गांव के बाहर निकली। दोनों बिना बताए ही निकलीं और पता नहीं क्यों दोनों ने मौत चुन ली? यह भी हो सकता है कि दोनों टहलने गई हों और उनके साथ हादसा हो गया है। शशि की ट्रेन में टांग कटकर अलग गिरी। वहीं, नीतू के सिर पर गहरी चोट लगी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शशि के भाई विनोद ने बताया कि मैं काम पर घर से बाहर गया था। दोनों सहेलियों के बीच कोई विवाद नहीं है। लोगों ने मुझे बताया कि ट्रेन से दो लड़कियां कट गई हैं।

# सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रदेश अग्रसर : सुरेश खन्ना

**संवाददाता**

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026–2027 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून–व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल विकास, किसानों की खुशहाली और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024–2025 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आकलित हुई है, जो वर्ष 2016–2017 की प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपये के मुकाबले दोगुने से अधिक है। वर्ष 2025–2026 में

प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रही है और बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। सुरेश खन्ना ने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018–2019 में 29वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2023–2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनसे करीब 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। इनमें से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है और देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में श्लीडर श्रेणीश का दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रस्तुत बजट प्रदेश को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के साथ विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

# मुख्यमंत्री योगी बोले, सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान पर आधारित है 2026-27 का बजट

**संवाददाता**

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026–27 के बजट को उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण की नवगाथा बताते हुए कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश ने अपनी छवि बदलने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज पोटेंशियल हब के रूप में उभरा है और देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना चुका है। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने यह बातें कहीं । मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष का बजट 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है, जो पिछले नौ वर्षों में तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है। बजट की थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम रखी गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 43,565 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए निर्धारित की गई है, जिससे निर्माण कार्यों के

माध्यम से रोजगार और विकास को गति मिलेगी। श्री योगी ने कहा कि यह उनकी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार किसी मुख्यमंत्री को लगातार दसवीं बार बजट पेश करने का अवसर मिला है। उन्होंने दावा किया कि बीते नौ वर्षों में राज्य में कोई नया कर नहीं लगाया गया। कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन के कारण उत्तर प्रदेश को श्रेवेन्यू प्लसश राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश का अनुकूल वातावरण बना है। अब तक 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेहतर कानून–व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी ने निवेशकों और आम नागरिकों का विश्वास बढ़ाया है। तकनीकी क्षेत्र में प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे तथा एआई मिशन की भी शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तकनीक से समृद्ध राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए योगी ने कहा कि अन्नदाता को उद्यमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि में डीजल पंप सेट के माध्यम से सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई है और पीएम कुसुम योजना का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा है। प्रदेश की 44 चीनी मिलों के आधुनिकीकरण से लगभग 10 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें काशी और मिर्जापुर समेत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने खुद को श्अचीवर्स स्टेटश के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है और यह बजट उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट राज्य के समग्र, संतुलित और अवस्थापना–प्रधान विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि नीति आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स–2024 में उत्तर प्रदेश ने देश के लैंड–लॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य की निर्यात क्षमता और औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है।

# डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पंडित दीनदयाल को दी श्रद्धांजलि, योगी ने भी चित्र पर चढ़ाए फूल

**संवाददाता**

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। इसमें सीएम योगी को पहुंचना था लेकिन वह कैबिनेट बैठक और उसके बाद बजट सत्र के चलते नहीं पहुंच पाए। इसके बाद कार्यक्रम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। उन्होंने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को उत्तर प्रदेश सरकार साकार कर रही है। सीएम योगी की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मेयर सुषमा खर्कवाल, पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम चारबाग स्थित पंडित दीनदयाल स्मृतिका वाटिका में आयोजित किया गया। सीएम कार्यक्रम में नहीं पहुंचे लेकिन उन्होंने अपने सरकारी आवास पर ही पंडित दीनदयाल के चित्र पर फूल चढ़ाए। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, एकात्म मानववाद के प्रणेता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ में उनके

चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सशक्त राष्ट्र के निर्माण तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की ज्योति पहुंचाने का उनका संदेश हम सभी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। ब्रजेश पाठक ने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों के क्रम में यूपी सरकार हर गरीब को पक्का मकान, हर गरीब को जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं दे रही है। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा–सुमन अर्पित करता हूं। अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग कम से कम पंडितजी के एकता, मानववाद के सिद्धांत को जानें, समझें और उसको धरातल पर उतारें। भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। पंडितजी ने जनसंघ की स्थापना काल से लेकर अपने सिद्धांतों की बदौलत देश पर नई दिशा देने का काम किया था। आज उसको पूरा करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं।

# स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार, वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग

**संवाददाता**

लखनऊ। राजधानी के गोमतीनगर इलाके में कैफे की आड़ में स्पा सेंटर और देहव्यापार का धंधा चल रहा था। बुधवार को कई पीड़िताएं थाने पहुंची तब पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। इसके बाद कैफे संचालक कैफे बंद करके फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लखनऊ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आई एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। आरोपी ने धर्म छुपाकर दोस्ती की। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़िता ने बताया वह यूपी पुलिस की तैयारी करने लखनऊ आई थी। पार्ट टाइम जॉब की तलाश में थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल और कमर हयात इदरीसी नाम के युवकों से हुई। आरोप है कि दोनों ने उसे एक स्पा सेंटर में काम दिलाया। इस दौरान राहुल से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं। राहुल उसे अपने कमरे पर बुलाता था। एक दिन उसने उसे बीयर पिलाई और नशे की हालत में उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता का कहना है कि कुछ समय बाद राहुल उसे घूमने के लिए ले गया। जहां उसने उसका आधार कार्ड देख लिया। आधार कार्ड पर उसका नाम मोहम्मद कमरु जमाल लिखा था। हकीकत सामने आने पर वजह पूछी तो विवाद हो गया। पीड़िता ने बताया वह 2024 में जॉब की तलाश में लखनऊ आई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात राहुल नाम के व्यक्ति से हुई। जिसका असल नाम कमरू जमाल है। पार्लर में जॉब दिलाने के नाम पर साथ ले जाता है जबकि वह मेंस मसाज सेंटर होता है। इस दौरान नशे में कुछ अश्लील वीडियो बना ली जाती है। उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है। इसके बाद देव व्यापार में धकेल देते हैं। इसके दौरान कमर हयात आमिर, राहुल और अन्य लोग जिनका नाम में नहीं जानती वह लोग रेप करते हैं। अलग–अलग जिलों में ले जाकर गंदा काम करवाया। बाद में युवती को जानकारी मिली कि आरोपी के अन्य लड़कियों से भी संबंध हैं और वह उनके साथ रहने लगा। फिर युवती से बातचीत करना बंद कर दिया। मामले में इंस्पेक्टर गोमती नगर बृजेश चंद तिवारी का कहना है पीड़िता को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

# संक्षिप्त

## अग्निवीर भर्ती रैली का छठवां दिन, 13 जिलों के 823 अभ्यर्थी हुए शामिल

**संवाददाता**

लखनऊ। आर्मी भर्ती ऑफिस लखनऊ की ओर से छावनी स्थित एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली के छठे दिन, 11 फरवरी को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई। सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ स्टेडियम में जुटनी शुरू हो गई थी। इस दिन भर्ती में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की बिंदकी, फतेहपुर और खागा तहसील के साथ ही लखनऊ जिले की मलिहाबाद, बक्शी का तालाब (बीकेटी), लखनऊ, मोहनलालगंज और सरोजनीनगर तहसीलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अग्निवीर जीडी श्रेणी के लिए कुल 1170 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इनमें से 823 अभ्यर्थी भर्ती रैली में शामिल हुए, जो लगभग 70.34 प्रतिशत उपस्थिति रही। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। 12 फरवरी को अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए अगली भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इस दिन चित्रकूट जिले की कर्वी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर तहसील तथा कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद, डेरापुर, अकबरपुर, सिकंदरा, मैथा और भोगनीपुर तहसीलों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इंडियन आर्मी के अंतर्गत एआरओ लखनऊ उत्तर प्रदेश के 13 जिलों औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ की भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है।

# कुकरैल नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ का बजट

## लखनऊ में मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी खुलेगी, कैंसर संस्थान और प्रेरणा स्थल के लिए खोला खजाना

**संवाददाता**

लखनऊ। यूपी के बजट में योगी सरकार ने लखनऊ को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने शहर के विकास के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ के कुकरैल नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ का फंड दिया जाएगा। जियामऊ स्थित कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में बताया गया है कि लखनऊ में मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी खोली जाएगी। इसके अलावा, लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। सरकार को अनुमान है कि डिफेंस कॉरिडोर से पूरे प्रदेश में 53,263 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। कुकरैल नाइट सफारी 2027 एकड़ में तैयार की जा रही है। नाइट सफारी में 1,510 करोड़ रुपए का बजट लगेगा। सरकार ने पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए जारी किए थे। सरकार का कहना है कि इस सफारी को सिंगापुर की नाइट सफारी की तर्ज पर बनाया जाएगा। लखनऊ में बन रही कुकरैल नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा और अनुरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड जारी किया गया है। लखनऊ विकास क्षेत्र और प्रदेश के दूसरे विकास प्राधिकरणों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। अयोध्या, मथुरा, लखनऊ समेत 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण ऐशबाग लखनऊ में किया जा रहा है।डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना हेतु डन किए गए हैं। इनमें 35,280 करोड़ रुपए का निवेश और 53,263 लोगों को सीधे रोजगार का अनुमान है।महिला सामर्थ्य योजना के तहत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां खोली जानी थीं। गोरखपुर, बरेली और रायबरेली में काम शुरू भी हो गया है। प्रयागराज और लखनऊ में कंपनियों का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण,नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत मेरठ में 35 साल, आगरा में 33 साल, लखनऊ में 22 साल बाद नई आवासीय योजना लॉन्च की गई है। बुलंदशहर में पहली बार औद्योगिक योजना लॉन्च की गई है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालयों में दवाओं की व्यवस्था के लिए प्रदेश में 2 राजकीय औषधि निर्माण शालाएं लखनऊ और पीलीभीत में संचालित हैं। अब इनकी उत्पादन क्षमता में इजाफे का प्रयास किया जा रहा है। हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी, ट्रामा सेंटर, छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाया जाना है। 10 हजार टूरिस्ट गाइडों का कौशल विकास किया जाना है। इस योजना का लाभ लखनऊ को भी मिलेगा।

# किराना स्टोर में लगी आग, सारा सामान जलकर राख

**संवाददाता**

लखनऊ। राजधानी के यहियागंज इलाके में मंगलवार देर रात एक किराना दुकान में आग लग गई। आग लगते ही आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोग गली में निकल आए। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और अंदर रखे सामान धू–धूकर जलने लगे। इस दौरान दुकान से 10 फीट तक लपटें निकलीं। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने करीब 30 मिनट पर आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुकान से धुआं और लपटें उठती देख लोगों ने तुरंत चौक फायर स्टेशन को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के दौरान आसपास की दुकानों को एहतियातन खाली करा लिया गया था। राहत की बात यह रही कि घटना के समय दुकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, आग से दुकान में रखा लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो गए।आग मुजम्मिल की किराना दुकान में लगी। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है।

# वेव मॉल को फीते से नापा, पार्किंग एरिया में बना रखीं अवैध दुकानें, 7 दिन में हटाने का अल्टीमेटम

**संवाददाता**

लखनऊ। राजधानी के विभूतिखंड स्थित वेव मॉल में पार्किंग में 50 से अधिक अवैध दुकानें बना दी गईं। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की टीम बुधवार को फोर्स के साथ इनकी नपाई करने पहुंची। जोन–1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी और रवि नंदन के नेतृत्व में टीम ने मॉल परिसर और उसके चारों ओर बनी चार मंजिला इमारत की नाप–जोख की। वर्ष 2004 में बने इस मॉल की आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत हुई थी। शिकायत में आरोप है कि कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद भी भवन में मानचित्र से अलग निर्माण (डेविएशन) किया गया है। इसी आधार पर स्व.ने जांच कमेटी गठित कर नपाई शुरू कराई है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने लाउडस्पीकर के जरिए मॉल परिसर में संचालित अस्थायी दुकानों को अवैध बताते हुए अनाउंसमेंट भी किया। टीम ने मौके पर मौजूद मानचित्र को भी देखा। जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने

बताया थाना विभूतिखंड क्षेत्र में स्थित वेव मॉल के संबंध में डेविएशन की शिकायत प्राप्त हुई है। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के बाद निर्माण में बदलाव के आरोपों की जांच की जा रही है। फिलहाल फ्लोर–वाइज स्वीकृत प्लान मंगाया जा रहा है और इंजीनियरों की रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्रारंभिक जांच में कॉलम और बाउंड्री से संबंधित कुछ मामूली डेविएशन चिन्हित किए गए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पूरी नपाई और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना अनुमति या स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। वेव मॉल में नक्शे के विपरीत निर्माण होने पर नोटिस जारी किया जाएगा। अतिरिक्त निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।

# एसएससी–एमटीएस परीक्षा में छात्रों को नहीं मिली एंट्री, अभ्यर्थियों ने हंगामा किया

**संवाददाता**

लखनऊ। बीकेटी थाना क्षेत्र स्थित जीसीआरजी कॉलेज में बुधवार को एसएससी–एमटीएस परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया और न ही कोई स्पष्ट सूचना दी गई। दूर–दराज के जिलों से आए अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी

रही, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। सूचना न मिलने से नाराज छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि सर्वर ठप होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। हालांकि, छात्रों ने आरोप लगाया कि सर्वर की समस्या के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने समय रहते पुलिस को सूचित नहीं किया। ग्रामीणों की सूचना पर बीकेटी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाराज छात्रों को समझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित कर छात्रों को शांत कराया।

# नाबार्ड की 'ग्राम दुकान' से स्व-सहायता समूह की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

## हुनर, कौशल और लघु उद्यम को मिल रहा सशक्त मंच, जीवन स्तर में हो रहा सुधार

बीएनई

रायपुर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण बाजार स्थापित करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लकर महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित की है। इन बाजारों का उद्देश्य महिला स्व–सहायता समूहों को उनके हस्तनिर्मित उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संचालित 'ग्राम दुकान' पहल स्वसहायता समूह की महिलाओं के जीवन स्तर को उन्नत बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। राजनांदगांव स्थित पाताल भैरवी मंदिर के पास स्थापित ग्राम दुकान महिला समूहों के लिए अपने हुनर, कौशल एवं लघु उद्यम को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। इस ग्राम दुकान में महिला स्वसहायता समूह द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित विभिन्न उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें पूजा सामग्री, अचार, पापड़, मुरकू, नड्डा, बिजौरी, मुरब्बा, मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबुन, जिमीकंद, फूल, मशरूम, कपड़े, विविध खाद्य सामग्री, मसाले, दोना–पत्तल, डेकोरेशन आइटम्स तथा अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। महिला समूह अपने उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग कर ग्राम दुकान के माध्यम से उनका विक्रय कर रही हैं, जिससे उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है। ग्राम दुकान की संचालिका श्रीमती निशा मंडावी ने बताया कि पाताल भैरवी मंदिर के समीप स्थित होने के कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं से उत्पादों को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ग्राम दुकान योजना के अंतर्गत समूह की महिलाओं को नाबार्ड ने

निरूशुल्क दुकान उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री के लिए सुलभ और स्थायी मंच मिल गया है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। नाबार्ड की यह पहल महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट उदाहरण बन रही है।

# एयरटेल ने 'ओटीपी लीक से होने वाले फ्रॉड' रोकने के लिए नया एआई - आधारित सुरक्षा फीचर लॉन्च किया

बीएनई

देहरादून। एयरटेल ने स्पैम की समस्या से निपटने के अपने लगातार प्रयासों के तहत आज अपना नया एआई–पावर्ड फ्रॉड अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। यह फीचर ग्राहकों को ओटीपी (वन–टाइम पासवर्ड) से जुड़े बैंकिंग फ्रॉड से रियल–टाइम में सुरक्षित रखने में मदद करेगा। आजकल धोखेबाज़ डिलीवरी, कस्टमर सपोर्ट या अन्य रोज़मर्रा की सेवाओं का बहाना बनाकर ग्राहकों पर जल्दबाज़ी का दबाव बनाते हैं और उनसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा ओटीपी साझा करवा लेते हैं। जैसे ही ओटीपी साझा किया जाता है, ग्राहक के बैंक खाते में जमा राशि धोखाधड़ी के खतरे में पड़ जाती है। एयरटेल का नया एआई–पावर्ड सिस्टम ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों की पहचान कर ग्राहकों को समय रहते सचेत करता है। जब किसी संभावित जोखिम भरी इनकमिंग कॉल के दौरान बैंक द्वारा भेजा गया ओटीपी डिटेक्ट होता है, तो एयरटेल तुरंत 'फ्रॉड अलर्ट' के ज़रिये ग्राहक को चेतावनी देता है कि कॉल पर रहते हुए बैंकिंग ट्रांजैक्शन का ओटीपी साझा करना जोखिम भरा हो सकता है। इस मौके पर एयरटेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शाश्वत शर्मा ने कहा,"हम एयरटेल को एक सुरक्षित नेटवर्क बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस दौरान हमने महसूस किया है कि

डिजिटल लेन–देन को सुरक्षित रखने में ओटीपी की अहम भूमिका होने के बावजूद, अपराधी अलग–अलग तरीकों से इसकी उपयोगिता को कमजोर कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमें एयरटेल के नेटवर्क स्तर पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसे बैंकिंग फ्रॉड से सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। हमारा नया, एआई–पावर्ड और स्वतः संचालित समाधान नेटवर्क स्तर पर पहले से सक्रिय रूप से काम करता है और रियल–टाइम में धोखाधड़ी की पहचान कर उसे रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। व्यापक परीक्षणों में इस समाधान ने ऐसे स्कैम्स को रोकने में उच्च स्तर की सटीकता और प्रभावशीलता दिखाई है।" पिछले दो वर्षों में एयरटेल ने एआई–आधारित कई सुरक्षा उपाय शुरू किए हैं, जैसे स्पैम कॉल अलर्ट और खतरनाक लिंक को ब्लॉक करना, ताकि फ्रॉड को शुरुआत में ही रोका जा सके। इन प्रयासों से नेटवर्क पर फ्रॉड में काफी कमी आई है, लेकिन ठग अब भी नकली पहचान और मनोवैज्ञानिक दबाव के ज़रिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह नया फीचर ऐसे ही खतरों से मोबाइल यूज़र्स को बचाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह समाधान फिलहाल हरियाणा में सक्रिय है और एयरटेल इसे अगले दो हफ्तों में अपने सभी ग्राहकों के लिए चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगा।

# संक्षिप्त

## अभिषेक शर्मा दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, नामीबिया के खिलाफ मैच में खेलने पर सस्पेंस

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय टीम के फ्लेम्बॉयंट ओपनर अभिषेक शर्मा पेट की समस्या के चलते दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने पिछले दो दिनों से अस्पताल में रहकर इलाज कराया है। टीम प्रबंधन ने बताया कि पेट की समस्या के कारण उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और अभी तक यह साफ नहीं है कि उन्हें आज यानी बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल पाएगी या नहीं। नामीबिया मैच पर असर अभिषेक शर्मा की फिटनेस को देखते हुए भारत बनाम नामीबिया मैच में उनके खेलने पर सस्पेंस है। यह मैच 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होना है। बीसीसीआई के सूत्र ने कहा, श्मैच के लिए उनकी उपलब्धता अभी स्पष्ट नहीं है।श टीम को उम्मीद है कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर मैदान पर वापसी करेंगे। नामीबिया के खिलाफ अभिषेक की जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। वहीं, ईशान किशन दूसरे ओपनर हो सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की उम्मीद! टीम प्रबंधन और मेडिकल स्टाफ यह आश्वस्त हैं कि शर्मा 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। उनका स्वास्थ्य और रिकवरी इस समय मुख्य प्राथमिकता है। गंभीर के घर डिनर पर गए थे सूत्रों के मुताबिक, 25 वर्षीय अभिषेक शर्मा ने संडे को मुख्य कोच गौतम गंभीर के घर आयोजित डिनर में हिस्सा लिया था, लेकिन बाकी टीम के सदस्यों की तुलना में जल्दी ही वहां से चले गए थे।

# दौसा में कार-ट्रक की भीषण टक्कर, छह लोगों की हुई दर्दनाक मौत

एजेंसी

दौसा। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 5 सगे भाई और उनके एक दोस्त की मौत हो गई। सभी युवक शादी–समारोह से लौटकर घर जा रहे थे। जयपुरदृआगरा नेशनल हाईवे पर कैलाई गांव के पास रात करीब 11 बजे उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ जा रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे से कुछ घंटे पहले सभी दोस्त शादी समारोह में साथ बैठकर खाना खा रहे थे और उन्होंने एक साथ फोटो भी क्लिक करवाई थी। इसके बाद सभी एक ही कार में सवार होकर घर के लिए रवाना हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। मौके पर मची चीख–पुकार, परिवार और गांव में मातम हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव और परिजन बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने कार में फंसे युवकों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सभी युवक आपस में चाचा–भतीजे और एक ही परिवार के थे। क्रेन से हटाई गई कार, अस्पताल में एक–एक कर मौत की पुष्टि ट्रेलर में घुसी कार को क्रेन की मदद से अलग किया गया। इसके बाद कार में फंसे युवकों को अस्पताल ले जाया गया। सिकंदरा अस्पताल में 4 युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, 2 गंभीर घायलों को दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। इनमें से एक युवक ने दौसा में दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कार में बुरी तरह फंसे थे युवक टक्कर के बाद कार सवार युवक अंदर बुरी तरह फंसे हुए थे। ड्राइवर सीट पर बैठे युवक का शरीर हादसे के बाद आधा बाहर लटक गया था। हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। सभी युवक एक ही गांव और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान हादसे में समय सिंह (25) पुत्र राम सिंह योगी, लोकेश (24) पुत्र गोवर्धन योगी, दिलखुश (24) पुत्र बनवारी योगी, मनीष (23) पुत्र हरिमोहन योगी, अंकित (26) पुत्र लालाराम बैरवा और नवीन (23) की मौत हो गई। आभानेरी से लौट रहे थे सभी युवक पुलिस के मुताबिक, कार सवार सभी युवक कालाखो (दौसा) गांव के रहने वाले थे। वे मंगलवार को आभानेरी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे और लौटते समय यह हादसा हो गया। पुलिस का कहना है कि कार की रफ्तार तेज थी, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, कार डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। हाईवे पर लगा लंबा जाम हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर काफी देर तक जाम लगा रहा।

# कारोबार में खूब इस्तेमाल हो रहा AI, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा भारत, सुरक्षा अब भी चुनौती

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को अपनाने के मामले में दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा है। एंटरप्राइज एआई/एमएल के इस्तेमाल में अमेरिका के बाद भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। क्लाउड सुरक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जेडस्केलर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय उद्यमों ने जून से दिसंबर, 2025 के बीच कुल 82.3 अरब एआई/एमएल लेनदेन दर्ज किए। यह संख्या एशिया–प्रशांत क्षेत्र की कुल एआई गतिविधियों का 46.2 फीसदी है, जो भारत को इस क्षेत्र का निर्विवाद अगुवा बनाती है। भारत की यह वृद्धि 2025 में सरकार समर्थित निरंतर डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के साथ एआई बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में बड़े सार्वजनिक एवं निजी निवेश के बिल्कुल अनुरूप है। एआई–सक्षम कार्यबल के विस्तार और क्लाउड–फर्स्ट ढांचे ने पिछले वर्षों की तुलना में देश की इस उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान दिया है। क्लाउड–फर्स्ट ढांचे एआई सेवाओं का तेजी से प्रसार करने में मदद करते हैं। यह रिपोर्ट कंपनी के जीरो ट्रस्ट एक्सचेंज मंच पर जनवरी से दिसंबर, 2025 के बीच 1,000 अरब एआई/मशीन लर्निंग लेनदेन के विश्लेषण पर आधारित है। प्रौद्योगिकी–संचार क्षेत्र कर रहे वृद्धि की अगुवाई जेडस्केलर ने थ्रेटलैब्ज–2026 एआई सुरक्षा रिपोर्ट में कहा, भारत में एआई के बढ़ते उपयोग का नेतृत्व मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और संचार ने किया है। इन क्षेत्रों में 31.3 अरब लेनदेन हुए हैं। इसके बाद विनिर्माण (15.7 अरब), सेवा (12.6 अरब) और वित्त–बीमा (12.2 अरब) क्षेत्रों का

स्थान है। भारत में जेडस्केलर के सीआईएसओ–इन–रेजिडेंस सुब्रत सिन्हा ने कहा, देश में एंटरप्राइज एआई अपनाने का पैमाना अधिकांश संगठनों की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियों के पास संवेदनशील डाटा की जानकारी नहीं जेडस्केलर ने कहा, भारत में एआई की स्वीकार्यता की मजबूत गति के बावजूद सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें एजेंटिक एआई का हथियार के तौर पर इस्तेमाल और नवाचार–सुरक्षा उपायों के बीच बड़ा अंतर शामिल है। अपनाने की रफ्तार में तेजी के बावजूद कई संगठनों के पास अपने सक्रिय एआई मॉडल और उनमें शामिल खूबियों की बुनियादी सूची तक नहीं है। इस कारण उन्हें इस बात की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती कि उनका संवेदनशील डाटा कहां असुरक्षित है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पिचाई समेत दुनियाभर के दिग्गज होंगे शामिल रू यह रिपोर्ट दिल्ली में 16–20 फरवरी तक आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट–2026 से एक सप्ताह पहले आई है। इस सम्मेलन में एनवीडिया के जेन्सेन हुआंग, ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक के डारियो अमोदेई और क्वालकॉम के क्रिस्टियानो आमोन जैसे दुनिया के प्रौद्योगिकी दिग्गजों, नीति–निर्माताओं और नवोन्मेषकों के शामिल होने की उम्मीद है।

# एशिया के सुपर-रिच खरीदारों को साधने की होड़, निजी जेट कारोबार में तेज उछाल

एजेंसी

सिंगापुर शहर। एशिया के सबसे बड़े एविएशन और डिफेंस ट्रेड फेयर सिंगापुर एयरशो में इस बार निजी जेट उद्योग की बढ़ती ताकत साफ नजर आई। विमान निर्माता कंपनियां अब कमर्शियल एयरलाइंस के बजाय बेहद अमीर निजी ग्राहकों और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को साधनों की तैयारी कर रही हैं। इस रणनीति के तहत गल्फस्ट्रीम ने अपने फ्लैगशिप बिजनेस जेट जी700 को प्रमुखता से प्रदर्शित किया, जिसकी कीमत करीब 7.5 से 8 करोड़ डॉलर (620–660 करोड़ रुपये) बताई जाती है। एयरशो परिसर में यात्री विमानों और सैन्य एयरक्राफ्ट से अलग खड़े इस निजी जेट को देखने को लंबी कतारें लगी रहीं। बीबीसी के मुताबिक, विमान के भीतर संभावित ग्राहकों के साथ सौदे को लेकर बातचीत चलती रही, जिससे साफ है कि एशिया में सुपर–रिच खरीदारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। विमान में पैनोरमिक खिड़कियों से आती रोशनी हल्के रंग की लेदर सीटों और पॉलिश्ड लकड़ी के वेनियर पर पड़ती है। केबिन में अलग–अलग लिविंग एरिया हैं। टीवी कंसोल और पीछे की ओर शावर के साथ ग्रैंड सुइट मौजूद है। यह डिजाइन सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि उद्योग में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। बिजनेस एयरक्राफ्ट की मांग में बदलाव गल्फस्ट्रीम के वर्ल्डवाइड सेल्स प्रमुख स्कॉट नील ने कहा, हम बड़े कॉरपोरेशनों और हाई–नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए बिजनेस एयरक्राफ्ट की मांग में बड़ा बदलाव देख रहे हैं। अधिक कंपनियां वैश्विक स्तर पर कारोबार कर रही हैं और उन्हें ज्यादा जगहों तक यात्रा करनी पड़ती है। ऐसा करने का सबसे कुशल तरीका बिजनेस एयरक्राफ्ट है। बॉम्बार्डियर से दसॉ तक सभी कंपनियां आमने–सामने इस सेगमेंट में गल्फस्ट्रीम अकेला खिलाड़ी नहीं है। दसॉ, बॉम्बार्डियर, एम्ब्रेयर और टेक्सट्रॉन एविएशन जैसी कंपनियां भी अमीर ग्राहकों को लुभाने की दौड़ में हैं। हालांकि, पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर निजी विमानों की आलोचना भी हो रही है, लेकिन विमान निर्माताओं ने इसमें बड़ा कारोबारी अवसर देख लिया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक, एयरलाइंस आमतौर पर अपने खर्च से सिर्फ दो–चार फीसदी अधिक मुनाफा कमा पाती हैं। इसके उलट, निजी जेट कम संख्या में बिकते हैं, लेकिन उनकी कीमत बेहद ऊंची होती है। कंपनियां सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस प्रोग्राम्स से भी अतिरिक्त कमाई करती हैं। नई रणनीति कम थकान, ज्यादा आराम आज निजी जेट निर्माताओं के लिए यात्रियों की थकान कम करना बड़ा सेलिंग पॉइंट बन गया है। कंपनियां दावा कर रही हैं कि उन्होंने केबिन एयर प्रेशर सुधारा है। शोर कम किया है और इंटीरियर को ऐसे डिजाइन किया है कि लंबी उड़ानें ज्यादा आरामदेह बन सकें। यही तकनीकी सुधार और समय बचत की सुविधा आज के सुपर–रिच ग्राहकों को निजी विमान खरीदने की ओर तेजी से आकर्षित कर रही है। पांच साल में 70: से ज्यादा बढ़े सुपर–रिच एविएशन इंटेलिजेंस फर्म विंगएक्स के मुताबिक, 2025 में वैश्विक स्तर पर निजी जेट उड़ानों की संख्या 37 लाख रही, जो 2024 से 5 फीसदी और महामारी पूर्व स्तर से 35 फीसदी अधिक है। 2020 से 2025 के बीच दुनिया में अल्ट्रा हाई–नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 70 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है।

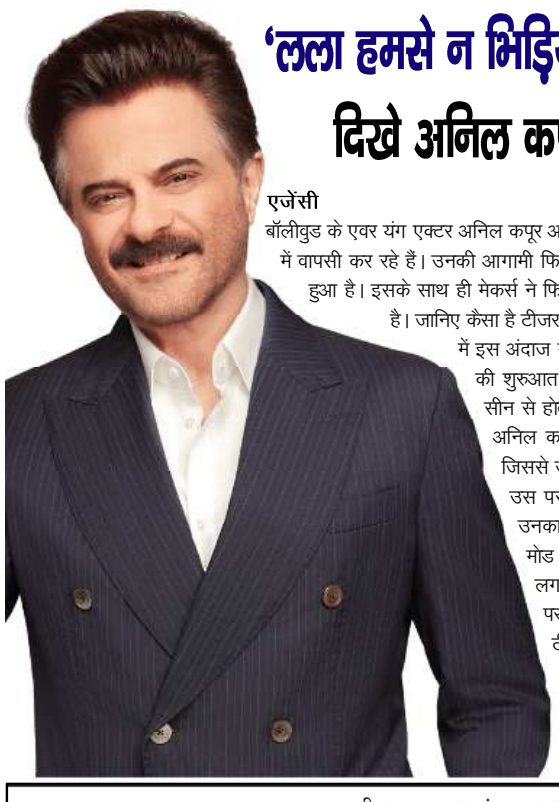

# 'लला हमसे न भिड़ियो', 69 साल की उम्र में एक्शन करते दिखे अनिल कपूर, 'सूबेदार' का टीजर हुआ रिलीज

एजेंसी

बॉलीवुड के एवर यंग एक्टर अनिल कपूर अब 69 साल की उम्र में एक्शन अवतार में वापसी कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म 'सूबेदार' का टीजर आज रिलीज हुआ है। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी जारी कर दी है। जानिए कैसा है टीजर और कब रिलीज होगी फिल्म? टीजर में इस अंदाज में दिखे अनिल कपूर फिल्म के टीजर की शुरुआत अनिल कपूर और फैसल मलिक के सीन से होती है। टीजर में दिखाया जाता है कि अनिल कपूर के आसपास कुछ ऐसा होता है, जिससे उन्हें गुस्सा आता रहता है। लेकिन वो उस पर काबू करते रहते हैं। लेकिन अंत में उनका गुस्सा फूट जाता है और वो एक्शन मोड में नजर आते हैं। टीजर देखकर ऐसा लगता है कि कहानी बुंदेलखंडी पृष्ठभूमि पर आधारित होगी।

टीजर में अनिल कपूर की आवाज में बुंदेलखंडी में डायलॉग भी सुनाई देता है। जिसमें वो कहते हैं कि 'लाला हमसे न भिड़ियो', जिसका मतलब है कि 'बेटा हमसे न टकराना।' 5 मार्च को रिलीज होगी फिल्म टीजर के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी जारी कर दी है। 'सूबेदार' 5 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म की कास्ट और कहानी के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल फैंस अनिल कपूर को इस नए अवतार में देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

अनिल कपूर के खाते में हैं कई फिल्में वर्कफ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर के खाते में कई फिल्में शामिल हैं। 'सूबेदार' के अलावा उनकी आगामी फिल्मों व सीरीज में 'अल्फा', 'किंग' और 'फैमिली बिजनेस' शामिल हैं। इसके अलावा उनके 'नायक 2' बनाने की भी चर्चाएं हैं। हाल ही में अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के बेबी शॉवर में नजर आए थे।

# भारत-ईयू एफटीए एक साल में लागू करने का लक्ष्य, वाणिज्य सचिव ने अमेरिका के साथ हुए समझौते पर ये कहा

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो रहे मुक्त व्यापार समझौते को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह बात जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों की दुनिया की प्रमुख प्रदर्शनी BIOFACH 2026 के दौरान कही। अग्रवाल ने भरोसा जताया कि यह समझौता अधिकतम एक वर्ष के भीतर लागू हो सकता है। समझौते को लेकर भारत और यूरोप में सकारात्मक माहौल अग्रवाल ने कहा कि इस समझौते को लेकर भारत और यूरोप दोनों में सकारात्मक माहौल है। जिससे भी बातचीत हुई, सभी इस एफटीए को लेकर उत्साहित हैं। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए नए अवसर खोलेगा। केवल व्यापार तक सीमित असर नहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच निवेश भी बढ़ेगा। बर्लिन में जर्मनी के कृषि मंत्री समेत यूरोपीय प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई कि भारत और ईयू की ताकतों को कैसे जोड़ा जाए। दोनों मिलकर विश्वस्तरीय सप्लाई चेन और वैश्विक शृंखला तैयार कर

सकते हैं अग्रवाल ने कहा कि यूरोप की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर विश्वस्तरीय सप्लाई चेन और वैश्विक मूल्य शृंखला तैयार कर सकती हैं, जो भारत और यूरोप के साथ–साथ वैश्विक बाजार को भी सेवा देंगी। समझौते की समयसीमा पर उन्होंने बताया कि आमतौर पर ऐसे समझौतों में कानूनी समीक्षा और यूरोप की सभी भाषाओं में अनुवाद जैसी प्रक्रियाएं समय लेती हैं। फिर भी दोनों पक्ष प्रक्रिया को तेज करने में जुटे हैं और अगले एक वर्ष के भीतर इसे लागू करने का लक्ष्य है। अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते में भारत ने अपने हितों की रक्षा की साथ ही उन्होंने भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी अहम बात कही। अग्रवाल ने बताया कि भारत ने व्यापार समझौतों में संवेदनशील क्षेत्रों की हमेशा रक्षा की है और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में भी किसानों, मछुआरों और डेयरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने बताया कि भारत सभी व्यापार समझौतों में स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ बातचीत करता है। जिन क्षेत्रों को देश के लिए अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, उन्हें बाजार पहुंच देने के मामले में भारत ने अपने साझेदार देशों को साफ संकेत दिया है कि ऐसे सेक्टर पूरी तरह नहीं खोले जा सकते। पिछले एक वर्ष में हुए कितने व्यापार समझौते? अग्रवाल ने कहा कि पिछले एक वर्ष में हुए पांच व्यापार समझौतों में सभी संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित रखा गया है। अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौते में भी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। जहां कुछ हद तक संवेदनशीलता थी, वहां टैरिफ रेट कोटा (TRQ) जैसे तंत्र का इस्तेमाल किया गया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
**सम्पादक-अंजू सिंह** (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743